

[2023] 10 एस. सी. आर 1133:2023 आई. एन. एस. सी 566

/

ममता देवी और ओआरएस।

बनाम

विश्वास सामान्य बीमा कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर.

(2023 की सिविल अपील संख्या 3904) 19 मई, 2023

/

[जे. के. माहेश्वरी और अरविंद कुमार, जे. जे.]

कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 -एस. 20-"विवादित दावा" के अंतर्गत जारी अधिसूचना-जब नहीं-मृत व्यक्ति जिसे दूसरे प्रतिवादी द्वारा ट्रक चालक के रूप में नियुक्त किया गया था, सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया और चोटों के कारण उसकी मौत हो गई- अपीलकर्ताओं द्वारा मांगी गई क्षतिपूर्ति-उसकी पत्नी, बेटे और माता-पिता-उप श्रम आयुक्त-सह-कर्मचारी मुआवजे के लिए आयुक्त को रु. 4,31,671-और 6 प्रतिशत ब्याज के साथ सम्मानित किया गया।पी. ए.-अपीलार्थियों द्वारा चुनौती दी गई-उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पुरस्कार स्वयं इस आधार पर अधिकार क्षेत्र के बिना था कि यह बीमाकर्ता द्वारा दायर लिखित बयान के कारण एक विवादित मामला था और यू/एस द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार एक प्रतिबंध था।20(1) & (2) - आयोजित किया गया:नियोक्ता ने अपीलकर्ताओं द्वारा दायर दावा याचिका में किए गए कथनों को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था-कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी-उल्लंघन करने वाले वाहन का बीमाकर्ता-प्रथम प्रतिवादी ने लिखित बयान दायर करने के बाद अपीलकर्ताओं और उनके गवाहों से जिरह नहीं की-इस प्रकार, मुआवजे की मांग करने वाले उनके द्वारा दायर दावे में उपयुक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अंतर्गत निर्धारित "विवादित दावे" का चरित्र नहीं होगा।20 (1) और (2) जहां खंड (क) के अंतर्गत श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों को अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले सभी आक्षेपित मामलों के दावों का न्यायनिर्णय न सौंपा गया था-इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि दावा याचिका उप श्रम आयुक्त-सह-आयुक्त के समक्ष बनाए रखने योग्य नहीं थी और अपीलकर्ताओं को अधिकार क्षेत्र श्रम न्यायालय के समक्ष अपनी शिकायत का पीछा करना था-आक्षेपित निर्णय को दरकिनार कर दिया गया-इसके अलावा, मृतक की पत्नी का अप्रतिरोध्य बयान कि वह प्रति माह 6,000 रुपये कमा रहा था, स्वीकार कर लिया गया-अपीलकर्ता दुर्घटना की तारीख से पहले से ही भुगतान/जमा की गई राशि को छोड़कर एक महीने से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ मुआवजे के हकदार हैं।

/

/

/

/

/

/

1133 ए.

1134

/

[2023] 10 एस सी आर।

सिविल अपील की अधिकारिता 2023 की सिविल अपील सं. 3904।

2014 के एम. ए. संख्या 777 में पटना में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 01.10.2018 से।

हर्ष पाराशर, अपीलार्थियों के लिए अधिवक्ता।

/

सुश्री साक्षी मित्तल, विष्णु मेहरा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए। न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अरविंद कुमार, जे।

/

अनुमति दी गई।

1. पटना में उच्च न्यायालय द्वारा 2014 की विविध अपील संख्या 777 में पारित किए गए निर्णय की शुद्धता और वैधता को चुनौती दी गई है, जिसके तहत, दावेदारों द्वारा दायर अपील, सी. डब्ल्यू. सी. संख्या 24 में उप श्रम आयुक्त-सह-कर्मचारी मुआवजे के लिए आयुक्त द्वारा पारित आदेश पर आरोप लगाते हुए, दावा याचिका को आंशिक रूप से अनुमति देते हुए, विरोधी पक्ष संख्या 1-रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (इसमें पहले प्रतिवादी) को रुपये के मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश देते हुए, इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि उठाया गया विवाद एक विवादित आदेश था।

/

मामला और यह गैर-न्यायिक है।

/

2. हमने अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अतिल इनाम के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री विष्णु मेहरा की दलीलें सुनी हैं और मामले के कागजातों का अध्ययन किया है।

3. अपीलकर्ता/दावेदार स्वर्गीय श्री वकील चौधरी की पत्नी, पुत्र और माता-पिता हैं, जिन्हें दूसरे प्रतिवादी द्वारा ट्रक चालक के रूप में नियुक्त किया गया था और रात को 21.04.2011 पर 10.30 पर सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे और दुर्घटना में लगी चोटों के परिणामस्वरूप उनकी मौत हो गई थी। इसलिए, नौकरी के दौरान हुई मृत्यु के कारण मुआवजे की मांग करते हुए और अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क देते हुए कि वह अपने नियोक्ता से मजदूरी के रूप में 6,000/- रुपये कमाता था, दावा याचिका श्रम उपायुक्त-सह-कर्मचारी मुआवजे के लिए उपायुक्त के समक्ष दायर की गई थी। नोटिस जारी होने पर, उल्लंघन करने वाले वाहन का बीमाकर्ता पेश हुआ और लिखित बयान दायर किया, लेकिन उसके बाद, उत्तरदाताओं द्वारा मामले को आगे नहीं बढ़ाया गया। ए होने वाले भौतिक साक्ष्य के आधार पर

/

/

/

1135

ममता देवी और ओ. आर. एस. बनाम विश्वास सामान्य बीमा कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर. [अरविंद कुमार, जे।] ए.

दावेदारों द्वारा प्रस्तुत, उप श्रम आयुक्त-सह-कर्मचारी मुआवजे के लिए आयुक्त ने दावे का निर्णय लिया और रुपये की राशि प्रदान की-और दुर्घटना की तारीख से राशि जमा होने तक प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया। उक्त क्षतिपूर्ति देने के लिए, न्यायाधिकरण ने मृतक की आय पर प्रति दिन Rs.150 पर विचार किया और 26 कार्य दिवसों के लिए कुल मासिक आय की गणना 3,900/- रुपये और उससे आधी, 1,950/- रुपये की गणना दावेदारों की आय के नुकसान के रूप में की और कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 (1923 का VIII) (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए 'डब्ल्यू. सी. अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत निर्धारित प्रासंगिक गुणक/कारक को 221.37 पर अपनाते हुए, तदनुसार कुल मुआवजे का निर्धारण किया।

/

/

4. इस पुरस्कार को दावेदारों द्वारा चुनौती दी गई थी क्योंकि निचले हिस्से में खराब होने के परिणामस्वरूप स्थिति खराब हो गई है।, पुरस्कार को स्वयं अधिकार क्षेत्र के बिना माना गया था।, उप श्रम आयुक्त-सह-कर्मचारी मुआवजे के लिए आयुक्त का इस आधार पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था कि बीमाकर्ता द्वारा लिखित बयान दायर किए जाने और डब्ल्यू. सी. अधिनियम की धारा 20 (1) और (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना के अनुसार प्रतिबंध होने के कारण यह एक विवादित मामला था।

/

5. अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (1) और (2) के अंतर्गत निहित शक्ति के आधार पर, उपयुक्त सरकार ने अधिसूचना जारी की थी, जिसके अंतर्गत खंड (ए) के अंतर्गत, श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों को अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले सभी विवादित मामलों के दावों का न्यायनिर्णयन सौंपा गया था।

/

6. जैसा कि आक्षेपित आदेश से देखा जा सकता है, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एकमात्र तर्क अपनाया गया कि उप श्रम आयुक्त-सह-कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था या वह तथ्य जो उच्च न्यायालय के दिमाग में दावा न करने के लिए था, वह प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा दायर लिखित बयान के कारण था, जो उप श्रम आयुक्त-सह-कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 और 2 भी थे।

/

/

7. हाथ में मौजूद अभिलेख से पता चलेगा कि उनके द्वारा दावा याचिका का आगे कोई विरोध नहीं था। दूसरी ओर, नियोक्ता ने दावेदारों द्वारा दायर दावा याचिका में किए गए कथनों को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था। दूसरे शब्दों में, कोई प्रतियोगिता नहीं थी। का बीमाकर्ता

/

1136

/

[2023] 10 एस सी आर।

ऐसा प्रतीत होता है कि लिखित बयान दायर करने वाले अपराधी वाहन ने दावेदारों और उनके गवाहों से जिरह नहीं की है। इस प्रकार, मुआवजे की मांग करने वाले दावेदारों द्वारा दायर दावा

डब्ल्यू. सी. अधिनियम की धारा 20 (1) और (2) के अंतर्गत उपयुक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अंतर्गत निर्धारित "विवादित दावे" के रूप में नहीं होगा। इस आधार पर, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचने में गलती कर गया कि दावा याचिका उप श्रम आयुक्त-सह-कर्मचारी मुआवजे के लिए आयुक्त के समक्ष विचारणीय नहीं थी और दावेदारों को अधिकार क्षेत्र वाले श्रम न्यायालय के समक्ष अपनी शिकायत को आगे बढ़ाना था।

/

8. सामान्य तौर पर, हम गुण-दोष के आधार पर अपील पर निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेज देते। हालाँकि, हम इस साधारण कारण से ऐसा करने से बचते हैं कि पहला दावेदार विधवा है, दूसरा दावेदार बेटा है और तीसरा और चौथा दावेदार मृतक के माता-पिता होने के कारण अभी भी उचित मुआवजे की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

/

/

9. इसलिए, हमने पक्षकारों की ओर से न्यायसंगत मुआवजे की मात्रा के मुद्दे पर उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, जिसे दावेदारों को दिए जाने की आवश्यकता है।

10. इस मोड़ पर, यह ध्यान रखना उचित और उचित होगा कि बीमाकर्ता अर्थात्, उप श्रम आयुक्त-सह-कामगार क्षतिपूर्ति आयुक्त द्वारा पारित पुरस्कार के अनुसरण में प्रथम प्रतिवादी ने विद्वान वकील द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए पुरस्कार राशि को जमा कर दिया है। बीमाकर्ता ने उप श्रम आयुक्त-सह-कामगार क्षतिपूर्ति आयुक्त द्वारा दिनांक 10.10.2014 द्वारा पारित पुरस्कार पर भी हमला नहीं किया। दूसरे शब्दों में, इसने अपने दायित्व को स्वीकार किया और कहा जाता है कि उसने पारित पुरस्कार को संतुष्ट किया है। जब यह तथ्यात्मक स्थिति है, तो हमें आवश्यक रूप से इस बात की जांच करनी होगी कि क्या दावेदारों के पक्ष में दिया गया मुआवजा वैधानिक अधिदेश के संदर्भ में है।

/

/

11. सामाजिक न्याय के वितरण की परिकल्पना करने वाले अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उप श्रम आयुक्त-सह-कर्मचारी मुआवजे के लिए आयुक्त इस निष्कर्ष पर पहुँचने में गलती कर गए कि दावेदारों की आय 3,900/- रुपये प्रति दिन या गणना की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी Rs.150 प्रति दिन होनी चाहिए।

/

/

ममता देवी और ओ. आर. एस. बनामविश्वास सामान्य बीमा कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर.
[अरविंद कुमार, जे।] ए.

आय।नियोक्ता द्वारा दाखिल किया गया लिखित विवरण इसका पूरा जवाब होगा, क्योंकि नियोक्ता द्वारा यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाता है कि मृतक को वेतन के रूप में 6,000/- रुपये प्रति माह मिल रहे थे। मृतक एक ट्रक चालक था और वर्ष 2011 में उसकी मृत्यु के समय उसके पास खाने के लिए चार मुँह थे। कल्पना के किसी भी विस्तार से, यह नहीं माना जा सकता है कि वह जो आय अर्जित कर रहा था, जैसा कि उसकी पत्नी ने शपथ पर दिए गए अपने बयान में दावा किया था, उसे अत्यधिक माना जा सकता है या वर्ष 2011 में एक ट्रक चालक द्वारा अर्जित मजदूरी के अनुरूप नहीं है।

/

12. इस प्रकार, हमें जो अटूट निष्कर्ष निकालना है, वह यह है कि मृतक की पत्नी का निर्विवाद बयान, जिसने अपदस्थ कर दिया था कि उसका पति 6,000/- रुपये प्रति माह कमा रहा था, सुसमाचार सत्य के रूप में स्वीकार किए जाने के योग्य है। हम उनके बयान पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। 13. वन आधारित चर्चा के आलोक में, मुआवजे की मात्रा का पुनर्निर्धारण मृतक की आय 6,000 रुपये करके करना होगा और दावेदारों को आय के समान नुकसान का 50 प्रतिशत घटाकर 3,000 रुपये प्रति माह करना होगा और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मृतक अपनी आकस्मिक मृत्यु के समय 22 वर्ष का था, उपयुक्त गुणक 221.37 होगा। इस प्रकार, दावेदार जो मुआवजे के हकदार होंगे, वह 3,000 रुपये एक्स 221.37 होगा जो कि रु. 6,64,110- (केवल छह लाख चौंसठ हजार एक सौ दस रुपये) के बराबर है।

/

/

/

14. जहां तक ब्याज के भुगतान का संबंध है, अधिनियम का अधिदेश स्पष्ट और स्पष्ट है, दावेदार दुर्घटना की तारीख के एक महीने बाद से भुगतान की तारीख तक प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से ब्याज के हकदार होंगे। इस प्रकार, दावेदार तदनुसार ब्याज के हकदार होंगे, उस राशि को छोड़कर जिसे पहले प्रतिवादी-बीमाकर्ता द्वारा भुगतान या जमा किया गया है।

/

15. वनहीन कारणों के लिए, हम इस अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं और पटना में उच्च न्यायालय द्वारा 2014 के विविध आवेदन संख्या 777 में पारित किए गए आक्षेपित

निर्णय को दरकिनार करते हैं और दुर्घटना की तारीख से भुगतान की तारीख तक एक महीने से पहले ही भुगतान या जमा की गई राशि को छोड़कर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ रु.

/

/

1138

/

[2023] 10 एस सी आर।

16. शेष राशि प्रथम प्रत्यर्थी-बीमाकर्ता द्वारा 2011 के सी. डब्ल्यू. सी. मामले में उप श्रम आयुक्त-सह-कर्मचारी मुआवजे के लिए आयुक्त, मगध प्रभाग, गया के समक्ष इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से छह सप्ताह के भीतर तेजी से और किसी भी दर पर जमा की जाएगी।

/

17. खर्चों में आसानी होती है।

दिव्या पांडे

अपील की आंशिक रूप से अनुज्ञात है।

(सहायक: रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

/

/

/

/

/

/

/